



पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट 'कल्पसर प्रोजेक्ट' को मिले नीदरलैंड की तकनीक के नए पंख

पंजाब से बिहार-यूपी होते हुए बंगाल तक चलेगी नई ट्रेन, रूट में शामिल हैं कौन से 35 स्टेशन ? प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से 'कल्पसर परियोजना' को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति गुजरात की पानी की जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी कल्पसर परियोजना प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नीदरलैंड दौरे के दौरान कल्पसर परियोजना के लिए तकनीकी सहयोग को लेकर आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए गुजरात को जल संसाधन के क्षेत्र में नीदरलैंड के तकनीकी सहयोग और विशेषज्ञता का लाभ मिलेगा सरदार सरोवर बांध पर निर्भरता होगी कम, पेयजल और सिंचाई के लिए सुनिश्चित होगी जल की व्यापक उपलब्धता (जीएनएस)। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों से गुजरात की महत्वाकांक्षी

कल्पसर परियोजना को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। नीदरलैंड के अपने दौरे के दौरान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने रविवार को नीदरलैंड के प्रधानमंत्री श्री रॉब जेटेन के साथ नीदरलैंड की प्रसिद्ध जल प्रबंधन संरचना, 'अफरस्टुइडिज्क' का दौरा किया। उन्होंने इस बांध में इस्तेमाल की गई तकनीक को सीखने योग्य बताया। उल्लेखनीय बात यह है कि 'अफरस्टुइडिज्क' और गुजरात की कल्पसर परियोजना के बीच बहुत-सी समानताएँ हैं। कल्पसर परियोजना पर तकनीकी सहयोग के लिए प्रधानमंत्री की मौजूदगी में भारत के जल शक्ति मंत्रालय और नीदरलैंड के बुनियादी ढांचा और जल प्रबंधन मंत्रालय के बीच आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इससे परियोजना का कार्य तेज रफ्तार से आगे बढ़ने के नए द्वार खुल गए हैं। अनियमित वर्षा और सूखे की समस्या से वर्षों से जूझ रहे गुजरात को सरदार सरोवर बांध के निर्माण से राहत तो मिली है, लेकिन दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किसी एक परियोजना पर ही निर्भर रहना जोखिम ही कहा जा सकता है।

इसीलिए, तत्कालीन मुख्यमंत्री और मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने खंभात की खाड़ी में महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना की संकल्पना की थी। हालांकि, यह परियोजना तकनीकी रूप से अत्यंत जटिल और चुनौतीपूर्ण है। **कल्पसर परियोजना** कल्पसर परियोजना के अंतर्गत खंभात की खाड़ी में एक विशाल बांध का निर्माण कर समुद्र में गिर रही सात नदियों के पानी का उपयोग करने की योजना है। इस योजना का उद्देश्य खंभात की खाड़ी पर मीठे पानी का एक विशाल जलाशय बनाना है, जिसमें ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन, सिंचाई और परिवहन इंफ्रास्ट्रक्चर का एकीकृत विकास शामिल है। वर्ष 2004 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के करकमलों से कल्पसर बांध की पररेखा सुनिश्चित करने के लिए भावनगर में समुद्री सर्वेक्षण का ऐतिहासिक शुभारंभ किया गया। लेकिन, योजना के बेहद जटिल होने के कारण इसे साकार करने में कई प्रकार की मुश्किलें सामने आ रही हैं। इन मुश्किलों से निपटने के लिए सरकार की ओर से लगातार दोस प्रयास किए जा रहे हैं। हाल ही में, 30 मार्च, 2026 को गांधीनगर, कल्पसर परियोजना के नीदरलैंड की राजदूत सुश्री मारिसा गेराड्स से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल ने कल्पसर योजना को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की थी।

यह सौभाग्य की वजह से है कि 'अफरस्टुइडिज्क' नीदरलैंड ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे मशहूर इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक है। यह दुनिया के लिए जल प्रबंधन का एक शानदार उदाहरण है। इसका निर्माण लगभग 80 साल पहले किया गया था। ये 32 किलोमीटर लंबा बैरियर डैम उत्तरी सागर को मीठे पानी की झील से अलग करता है। साथ ही, यह बांध नीदरलैंड के निचले इलाकों के बड़े हिस्से को भारी बाढ़ से बचाता है, यही वजह है कि इसे बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक मानक माना जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह समुद्र के खारे पानी को रोककर अंदर मीठे पानी का एक बहुत बड़ा जलाशय बनाता है। 'अफरस्टुइडिज्क' परियोजना में मीठे पानी के भंडारण के अलावा जहाजरानी, परिवहन संपर्क और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री का दृढ़ संकल्प और नीदरलैंड की भागीदारी करेगी कल्पसर परियोजना को साकार

यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी सदैव दीर्घकालीन और बड़े लक्ष्य लेकर आगे बढ़ते हैं। गुजरात में अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान उन्होंने कल्पसर परियोजना का स्वन देखा था। राज्य को जल संकट की स्थिति से बाहर निकालकर जल समृद्ध बनाने के संकल्प के साथ उन्होंने सरदार सरोवर बांध जैसी विराट परियोजना को धरातल पर उतारा। दशकों तक राजनीतिक और पंचायती राज अवरोधों का सामना कर रही सरदार सरोवर योजना को साकार करने के लिए उन्होंने अक्षय इच्छा शक्ति और फौलादी संकल्प का परिचय दिया। प्रधानमंत्री श्री मोदी कल्पसर योजना को लेकर शुरुआत से आशावादी रहे। प्रमाण प्रकाश की अड़चनों के बावजूद उन्होंने इस परियोजना को साकार करने के स्वन को आँखों से ओझल नहीं होने दिया। जटिल इंजीनियरिंग और तकनीक की विराट चुनौतियों के कारण परियोजना में विलंब अवश्य हुआ, लेकिन हाल के नीदरलैंड दौरे के दौरान उनका जल प्रबंधन संरचना 'अफरस्टुइडिज्क' का निरीक्षण करने जाना और कल्पसर परियोजना को धरातल पर उतारने की दिशा में भारत का नीदरलैंड के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर करना, यह बताता है कि

काफी महत्वपूर्ण कार्य किया है। **क्या है 'अफरस्टुइडिज्क'** 'अफरस्टुइडिज्क' नीदरलैंड ही नहीं, बल्कि दुनिया की सबसे मशहूर इंजीनियरिंग परियोजनाओं में से एक है। यह दुनिया के लिए जल प्रबंधन का एक शानदार उदाहरण है। इसका निर्माण लगभग 80 साल पहले किया गया था। ये 32 किलोमीटर लंबा बैरियर डैम उत्तरी सागर को मीठे पानी की झील से अलग करता है। साथ ही, यह बांध नीदरलैंड के निचले इलाकों के बड़े हिस्से को भारी बाढ़ से बचाता है, यही वजह है कि इसे बाढ़ नियंत्रण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर एक मानक माना जाता है। इसकी सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि यह समुद्र के खारे पानी को रोककर अंदर मीठे पानी का एक बहुत बड़ा जलाशय बनाता है। 'अफरस्टुइडिज्क' परियोजना में मीठे पानी के भंडारण के अलावा जहाजरानी, परिवहन संपर्क और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री का दृढ़ संकल्प और नीदरलैंड की भागीदारी करेगी कल्पसर परियोजना को साकार

प्रधानमंत्री कल्पसर परियोजना को लेकर कितने गंभीर और आशावादी हैं। इस बारे में भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा बयान में कहा गया है कि यह दौरा दोनों देशों की इस साझा प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है कि वे जल प्रबंधन के नवाचार, जलवायु अनुकूलन और सतत अवसंरचना के क्षेत्र में मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी का यह दौरा और कल्पसर परियोजना के लिए हुए आशय पत्र पर हस्ताक्षर से गुजरात के लिए सुनहरी संभावनाओं के नए द्वार खुल गए हैं। इसके साथ ही, नीदरलैंड अपने विश्व प्रसिद्ध 'अफरस्टुइडिज्क' डैम प्रोजेक्ट के 90 वर्षों से अधिक के प्रबंधन के अनुभव और निपुणता का लाभ भारत को देगा। यह सहयोग 29 मार्च, 2022 को दोनों देशों के बीच हुई 'जल पर भारत-डच रणनीतिक साझेदारी' पर आधारित है। बता दें कि नीदरलैंड के पास समुद्र में बांध बनाने की उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञता है, और अब गुजरात को इसी विशेषज्ञता का लाभ मिलने जा रहा है, जो राज्य की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना को साकार करने में अहम भूमिका निभाएगा।

संक्षिप्त समाचार

पीएम मोदी दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे स्वीडन, गोटेबर्ग एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन ने किया भव्य स्वागत
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दो दिवसीय दौरे पर स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे। एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की सीमा में प्रवेश करते समय पीएम मोदी के विमान को स्वीडिश गिपिन फाइटर जेट्स ने एस्कॉर्ट भी किया।

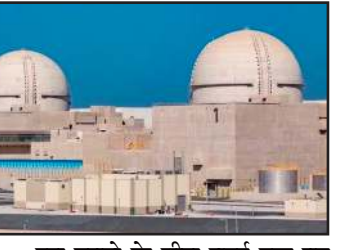


अबू धाबी के परमाणु प्लांट पर ड्रोन अटैक, बाल-बाल बचा अरब देश, किसने रची बड़ी साजिश ?

(जीएनएस)। संयुक्त अरब अमीरात के 'बराकह न्यूक्लियर पावर प्लांट' पर एक ड्रोन हमला हुआ है, जिससे वहां आग लग गई। गनीमत यह रही कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ और न्यूक्लियर सेफ्टी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। यह हमला ऐसे समय में हुआ है जब अमेरिका-इरान और इजरायल के बीच तनाव बहुत बढ़ा हुआ है। प्रशासन के मुताबिक, आग बाहरी सुरक्षा घेरे में मौजूद एक जनरेटर में लगी थी और प्लांट के सभी हिस्से सुरक्षित रूप से काम कर रहे हैं। अबू धाबी के इस परमाणु प्लांट पर पहली बार ऐसा हमला हुआ है। अधिकारियों ने बताया कि ड्रोन हमले के बाद बाहरी सुरक्षा दीवार के पास

रखे एक जनरेटर में आग लग गई थी। अच्छी बात यह है कि इस घटना में कोई भी व्यक्ति घायल नहीं हुआ। न्यूक्लियर प्लांट के सुरक्षा सिस्टम पूरी तरह सुरक्षित हैं और रेडिएशन फैलने का कोई खतरा नहीं है। प्लांट सामान्य रूप से काम कर रहा है। **तनाव का माहौल और आरोप** इस हमले के लिए जिम्मेदार कौन है, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। हालांकि, इस इलाके में चल रहे अमेरिका-इरान युद्ध के बीच यूएई पर पहले भी कई मिसाइल और ड्रोन हमले हो चुके हैं। अधिकारियों का मानना है कि ऐसे हमलों के पीछे इरान का हाथ हो सकता है, जो अक्सर ऊर्जा और समुद्री रास्तों को निशाना बनाता आया है। **नया तेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट** इस हमले के बीच यूएई एक नए तेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रहा है। अबू धाबी के क्राउन प्रिंस ने सरकारी तेल कंपनी अब्जुड को इस काम को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। इस नई पाइपलाइन की मदद से यूएई 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज'

रास्ते पर निर्भर रहे बिना फुजैराह के जरिए अपना तेल निर्यात दोगुना कर सकेगा। यह प्रोजेक्ट अगले साल शुरू होगा। **बराकह न्यूक्लियर प्लांट का इतिहास** यह न्यूक्लियर पावर प्लांट अबू धाबी के रेतौले इलाके में सऊदी अरब की सीमा के पास स्थित है। इसे यूएई ने दक्षिण कोरिया की मदद से करीब 20 बिलियन डॉलर की लागत से बनाया था और यह साल 2020 में शुरू हुआ था। पूरे अरब क्षेत्र में यह पहला और एकमात्र चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो देश की बिजली जरूरतों को पूरा करता है। अमेरिका और इरान के बीच बातचीत रुकी हुई है, जिसके कारण तनाव चरम पर है। इरान ने 'स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज' के समुद्री रास्ते को बंद कर दिया है, जहां से दुनिया का 20% तेल और गैस गुजरता था। इस रास्ते के बंद होने से दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा तेल संकट पैदा हो गया है और इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं।



बोले सीएम योगी- 'राष्ट्रवाद' ही भाजपा के कार्यकर्ताओं का मूल संस्कार, कार्यकर्ता भी बन सकता पीएम, सीएम व अध्यक्ष

(जीएनएस)। गोरखपुर, सीएम योगी ने कहा कि लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। परिवारवाद, क्षेत्रवाद, मत और मजहब से ऊपर उठकर हमें देश के बारे में सोचना चाहिए। भाजपा यही करती है। उन्होंने कहा कि अकेले भाजपा ही ऐसी पार्टी है जिसमें एक बूथ का अध्यक्ष भी एक समय पार्टी का प्रदेश और देश का अध्यक्ष भी बन सकता है। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी बन सकता है। **मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस, सपा, राजद, टीएमसी, डीएमके या ऐसे ही भ्रष्टाचार में डूबे अन्य दलों के आचरण को समाज सम्मान नहीं देता है। भाजपा कार्यकर्ता को समाज में सम्मान इसलिए मिलता है कि इस पार्टी के कार्यकर्ता का आचरण ने राष्ट्रवाद और भारतीयता का आचरण मिलता है। भाजपा का कार्यकर्ता पार्टी के संस्थापकों के मूल्यों और आदर्शों पर चलते हुए देश की एकता और अखंडता के लिए शुचिता और पारदर्शिता से आचरण करता है। सीएम**

योगी रविवार को गोरखपुर के सहजनवा विधानसभा क्षेत्र स्थित तेनुआ टोल प्लाजा के समीप एक रिजॉर्ट में भाजपा के जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 के अंतर्गत पार्टी की जिला इकाई की तरफ से आयोजित इस प्रशिक्षण वर्ग में शामिल प्रतिभागियों को 'राष्ट्र प्रथम' के भाव से अनवरत आगे बढ़ते रहने को प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि देश की सुरक्षा, संस्कृति, सुशासन और समृद्धि को जोड़ने का काम करने वाली भाजपा एकलौती पार्टी है। केंद्र और भाजपा की राज्य सरकारों ने इसी को अपने कार्यक्रमों का आधार बनाया है। 'भाजपा का इतिहास और विकास' विषय पर केन्द्रित जिला प्रशिक्षण वर्ग के उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्थापना के 50 वर्ष से भी कम समय में भाजपा ने दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में केंद्र और देश के 22 राज्यों में राष्ट्रवाद की विचारधारा को लागू करने के अभियान को आगे बढ़ाया है। भाजपा देश ही नहीं दुनिया का एकमात्र राजनीतिक दल है जिसने हमेशा और मजबूती से यह घोषणा की है कि राष्ट्र प्रथम, दल द्वितीय और व्यक्ति का हित अंतिम होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र प्रथम के भाव से पार्टी के संस्थापकों ने जो मूल्य, आदर्श और संस्कार दिए हैं, उन्हीं का अनुसरण करते हुए कार्यकर्ता जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो देश ही नहीं दुनिया के भारतवासियों के सामने पार्टी के रूप में सिर्फ भाजपा का ही चेहरा और कमल का फूल चुनाव निशान सामने होता है।

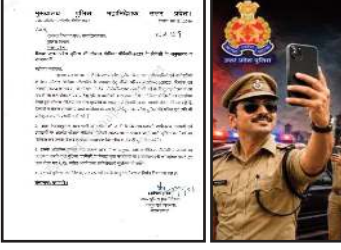


उ.प्र. में रीलबाज पुलिसकर्मियों की अब खैर नहीं, वर्दी में ठुमके लगाए तो नपेंगे, डीजीपी के आदेश पर मुख्यालय सख्त!

(जीएनएस)। उत्तर प्रदेश पुलिस में 'रील्स कल्चर' और सोशल मीडिया पर वर्दी की गरिमा को ताक पर रखने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मुख्यालय ने अब तक का सबसे सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। पुलिस मुख्यालय ने 15 मई 2026 को एक नया और बेहद कड़ा आदेश जारी किया है। आइए जानते हैं विभाग की ओर से जारी इस नए फरमान में क्या सख्त निर्देश दिए गए हैं। एडीजी कानून-व्यवस्था अमिताभ यश द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में स्पष्ट किया गया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए 'सोशल मीडिया पॉलिसी-2023' पहले से लागू है। इसके बावजूद यह आपत्तिजनक रील और कंटेंट पोस्ट किया जा रहा है, जिससे न केवल पुलिस की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि सरकारी कार्यों में भी बाधा उत्पन्न हो रही है। **विभागीय कार्रवाई के निर्देश**

देखा जा रहा है कि कई सेवारत और प्रशिक्षु पुलिसकर्मियों लगातार इस पॉलिसी की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नए आदेश के मुताबिक, अब सभी विभागाध्यक्षों और कार्यालय अध्यक्षों को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने अधीनस्थ जनपदों और इकाइयों में ऐसे पुलिसकर्मियों की पहचान करें जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। आदेश में साफ कहा गया है कि रील बनाने वाले या आपत्तिजनक सामग्री डालने वाले कर्मियों को चिन्हित कर उनके

विरुद्ध तत्काल आवश्यक विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। अब सिर्फ चेतावनी से काम नहीं चलेगा, बल्कि कड़ा एक्शन लिया जाएगा। **URL और स्क्रीनशॉट रखना अनिवार्य** पुलिस मुख्यालय ने तकनीकी स्तर पर भी तैयारी पुख्ता कर ली है। अब प्रत्येक माह एक निर्धारित प्रोफॉर्म के अनुसार रिपोर्ट तैयार की जाएगी। इसमें सोशल मीडिया पॉलिसी तोड़ने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी होगी। साथ ही, साक्ष्य के रूप में उस आपत्तिजनक पोस्ट का स्क्रीनशॉट और उसका वफ़्फ भी सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि विभागीय जांच के दौरान आरोपी कर्मी मुकर न सके।



इंटरनेशनल कोर्ट को भारत ने दिखाई औकात, फैसले को कूड़ेदान में फेंका, टेंशन में पाकिस्तान

(जीएनएस)। भारत और पाकिस्तान के बीच पानी के बंटवारे को लेकर चल रहा विवाद एक बार फिर गरमा गया है। हेग की एक अदालत (कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन) ने नदी के पानी को रोकने की क्षमता (मैक्सिमम पॉन्डेज) पर एक नया फैसला सुनाया है, जिसे भारत ने सिरे से खारिज कर दिया है। भारत का कहना है कि यह फैसले का कोई कानूनी मतलब नहीं रह जाता। भारत के लिए यह फैसला पूरी तरह 'शून्य' यानी बेकार है। आतंकवाद पर संधि को **किया है सरसंघ** पिछले साल पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने एक बड़ा कदम उठाया था। भारत ने साफ कह दिया था कि जब तक पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद नहीं करता, तब तक सिंधु जल संधि रुकी (सरसंघ) रहेगी और भारत पानी के नियमों को मानने के लिए मजबूर नहीं है।

पाकिस्तान के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। हावड़ा स्टेशन के बाहर बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, जहां गंगा घाट और बस स्टैंड के पास बनी अवैध दुकानों को पूरी तरह हटा दिया गया। लंबे समय से इस इलाके में सड़क और फुटपाथ पर दुकानदारों ने कब्जा कर रखा था और कई जगह अस्थायी ढांचे बनाकर जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था।

पाकिस्तान के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। हावड़ा स्टेशन के बाहर बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, जहां गंगा घाट और बस स्टैंड के पास बनी अवैध दुकानों को पूरी तरह हटा दिया गया। लंबे समय से इस इलाके में सड़क और फुटपाथ पर दुकानदारों ने कब्जा कर रखा था और कई जगह अस्थायी ढांचे बनाकर जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था।

हावड़ा स्टेशन के बाहर आधी रात चला बलडोजर, दिल्ली घाघ-अग्निमित्रा के बयानों से गरमाई सियासत

पश्चिम बंगाल में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। हावड़ा स्टेशन के बाहर बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया, जहां गंगा घाट और बस स्टैंड के पास बनी अवैध दुकानों को पूरी तरह हटा दिया गया। लंबे समय से इस इलाके में सड़क और फुटपाथ पर दुकानदारों ने कब्जा कर रखा था और कई जगह अस्थायी ढांचे बनाकर जमीन पर अवैध कब्जा किया गया था।





नवसर्जन संस्कृति हिन्दी



JioTV
CHENNAL NO. 2063



Jio Air Fiber



Jio tv +



Jio Fiber



Daily Hunt



ebaba Tv

Dish Plus



DTH live OTT



Rock TV



Airtel



Amezone Fire



Rocu Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही नवसर्जन संस्कृति हिंदी चैनल देखिये

यूपी में अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय बढ़कर हुआ 17 हजार, लोकभवन में सीएम योगी ने वितरित किए चेक

(जीएनएस)। लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विद्यालयों में बच्चों को जरूरत से ज्यादा संवेदनशील या छुईमुई बनाने के बजाय उन्हें मजबूत, अनुशासित और आत्मनिर्भर बनाने पर ध्यान देना चाहिए। यदि बच्चे स्कूल में स्वच्छता या अन्य जिम्मेदारी वाले कार्यों में सहयोग करते हैं तो उसे नकारात्मक रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। बच्चों में अनुशासन, जिम्मेदारी और श्रम के प्रति सम्मान की भावना विकसित करना शिक्षा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में यदि कोई शिक्षक बच्चों को स्वच्छता जैसे कार्यों से जोड़ता है तो उसे दंडित करने के बजाय सम्मानित किया जाना चाहिए। रविवार को लोकभवन सभागार में आयोजित 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों के सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री ने अंशकालिक अनुदेशकों को बढ़े हुए मानदेय का प्रतीकात्मक चेक भी वितरित किया। बताया कि वर्ष 2011-12 में छह से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 41,307 अंशकालिक अनुदेशकों की नियुक्ति की गई थी। उस समय सात हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय था। वर्तमान में 24,296 अनुदेशक सेवाएं दे रहे हैं। वर्ष 2011-12 से 2022 तक मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। वर्ष 2019 में अनुदेशक महासंघ के साथ बैठक में इस पर चर्चा हुई थी, लेकिन चुनाव अधिसूचना के कारण निर्णय नहीं हो सका। वर्ष 2022 में सरकार ने दो हजार रुपये की वृद्धि की

थी, लेकिन अब मानदेय बढ़ाकर 17 हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया गया है। साथ ही अनुदेशकों को केशलेस स्वास्थ्य बीमा सुविधा भी दी गई। निर्देश दिया कि बेसिक शिक्षा परिषद के पोर्टल पर जल्द पंजीकरण कराए ताकि अगले सप्ताह स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा सकें। कहा कि कई स्कूलों में छात्र संख्या कम होने के कारण

18 अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए गए हैं, जहां 18 हजार बच्चों के रहने और पढ़ने की व्यवस्था है। इसी तर्ज पर हर जिले में दो-दो मुख्यमंत्री कंपोजिट विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को 12वीं तक अपग्रेड किया जा रहा है और सभी 825 विकासखंडों में नए



अनुदेशकों की सेवाएं समाप्त करने के प्रस्ताव आए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें अस्वीकार कर 'स्कूल चलो अभियान' और 'आपरेशन कायाकल्प' शुरू किया। आज 96 प्रतिशत विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं। ड्रॉपआउट दर 17-18 प्रतिशत से घटकर लगभग तीन प्रतिशत रह गई है और लक्ष्य इसे शून्य तक पहुंचाने का है। सरकार बच्चों को यूनियन, जूते-मोजे, स्वेटर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। अभिभावकों के खालों में सीधे धनराशि भेजी जा रही है और पुस्तकें भी समय पर उपलब्ध कराई जाएंगी। श्रमिकों और निराश्रित बच्चों के लिए

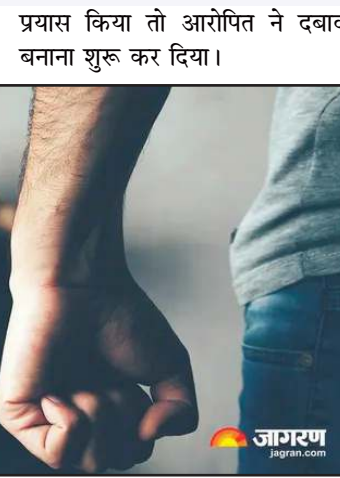
बुके नहीं, बुक से सम्मान बेसिक शिक्षा विभाग ने समारोह में पारंपरिक बुके की जगह पुस्तकों को सम्मान का माध्यम बनाकर एक नई और प्रेरक पहल की। मुख्यमंत्री को राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की प्रसिद्ध कृति रश्मिर्थी और संस्कृत के चार अध्याय पुस्तक भेंट की गई। वहीं उप मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री को शिवाजी सावंत की पुस्तक युगंधर भेंट की गई। प्रतीकात्मक चेक देकर भरोसे का संदेश लखनऊ समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी अनुदेशकों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। बढ़ा हुआ मानदेय पहले ही अनुदेशकों के खालों में भेज दिया गया है। कार्यक्रम में 14 अनुदेशकों को प्रतीकात्मक चेक देकर सरकार ने उनके प्रति अपने सहयोग और सम्मान का संदेश दिया। इनमें गोरखपुर, वाराणसी, अयोध्या, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, बाराबंकी, सीतापुर, हमीरपुर, लखनऊ, अलीगढ़, उन्नाव और हरदोई के अनुदेशक शामिल रहे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षकों के पास 'न्यूज और व्यूज' दोनों होते हैं। सरकार ने अनुदेशकों का मानदेय लगभग दोगुना बढ़ाया है और आगे भी उनके हित में काम किया जाएगा। कहा कि वह स्वयं वकील हैं और शिक्षकों की पैरवी आगे भी करते रहेंगे। वहीं, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि अनुदेशकों ने कभी टकराव या विरोध का रास्ता नहीं अपनाया, इसलिए सरकार भविष्य में भी उनके हित में सकारात्मक निर्णय लेती रहेगी।

विद्यालयों के लिए धनराशि जारी कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों के सभी बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाएगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने विभाग की उपलब्धियां गिनाई, जबकि कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडेय ने कहा कि अनुदेशकों की लंबे समय से चली आ रही मानदेय बढ़ाने की मांग अब पूरी हो गई है। कार्यक्रम में समग्र प्रगति पत्र का विमोचन भी किया गया। विधान परिषद सदस्य इंजीनियर अरविश कुमार सिंह, लालजी प्रसाद निर्मल, विधायक नीरज बोरा व अपर मुख्य सचिव पार्थ साश्वती सेन शर्मा समेत कई लोग मौजूद रहे।

लखनऊ: राजू बनकर आमिर ने युवती से की दोस्ती, दुष्कर्म के बाद बनाया मतांतरण का दबाव और 25 हजार भी एंटे

(जीएनएस)। लखनऊ। चिनहट इलाके में मुस्लिम युवक ने राजू नाम बताकर युवती को प्रेम जाल में फंसाया। फिर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करते हुए अश्लील वीडियो बना लिया। आरोपिक का धर्म पता चलने पर पीड़िता ने दूरी बनायी तो उसने ब्लैकमेल करते यौन शोषण किया। शादी की बात करने पर मतांतरण करने का दबाव बनाया। इनकार पर वीडियो डिलीट करने के एवज में 25 हजार एंटे लिए। मुकरने पर पीड़िता ने विरोध किया तो परिवार संग मिलकर पीटा। डीसीपी पूर्वी दीक्षा शर्मा के आदेश पर चिनहट पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है। यह है पूरा मामला चिनहट निवासी 20 वर्षीय युवती

ने बताया कि राजू शादी के नाम पर यौन शोषण करता रहा। इस दौरान प्रयास किया तो आरोपित ने दबाव बनाया शुरू कर दिया। पीड़िता का वीडियो व फोटो मोबाइल पर दिखायी। ब्लैकमेल करते हुए उसने यौन शोषण का दबाव बनाया। पीड़िता ने शादी की बात कही तो आरोपित ने मतांतरण की बात



आरोपित ने उसका अश्लील वीडियो बना लिया था। कुछ दिन बाद पीड़िता को पता चला कि आरोपित राजू मुस्लिम है। उसका असली नाम आमिर है। पीड़िता ने दूरी बनाने का

कही। बोला कि मतांतरण करने पर निकाह कर लेगा। इनकार करते हुए पीड़िता ने वीडियो डिलीट करने की मांग की। इसपर आरोपित ने 10 मई को उसे बुलाया। वीडियो डिलीट करने के एवज में 25 हजार रुपये की मांग की। व्यवस्था कर पीड़िता रुपये लेकर आरोपित के घर गयी। रुपये देने के बाद पीड़िता ने वीडियो डिलीट करने को कहा तो आरोपित ने उसकी पिटाई कर दी। 'चौखण्ड' मचने पर आरोपित के माता, पिता, भाई व बहन आए। गाली-गलौज करते हुए सभी ने पीड़िता को बेरहमी से पीटा। जिसमें वह चोटिल हो गयी। इस्पेक्टर दिनेश चंद्र मिश्र ने बताया कि आरोपित की तलाश की जा रही है।

लखनऊ यूनिवर्सिटी: 37 केंद्रों पर होंगी एलएलबी की परीक्षाएं, परीक्षा नियंत्रक ने जारी की लिस्ट

(जीएनएस)। लखनऊ विश्वविद्यालय ने एलएलबी तीन वर्षीय और एलएलबी इंटीग्रेटेड (पांच वर्षीय) पाठ्यक्रम की सम सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए केंद्रों की सूची जारी कर दी है। यह परीक्षाएं लखनऊ सहित संबद्ध पांच जिलों में बनाए गए 37 केंद्रों पर आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं के व्यवस्थित संचालन के लिए 17 नोडल सेंटर भी बनाए गए हैं। 37 परीक्षा केंद्रों पर 54 कालेजों के एलएलबी के छात्र-छात्राओं का केंद्र



आवंटित किया गया है। परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी की ओर से जारी केंद्रों की सूची के अनुसार हरदोई में छह, लखीमपुर

खीरी चार, रायबरेली दो, सीतापुर पांच और लखनऊ में 20 महाविद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। एलएलबी तीन वर्षीय छठे सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 मई से 13 जून, चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 26 मई से 16 जून तक होंगी। वहीं, एलएलबी इंटीग्रेटेड चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 मई से 15 जून, छठे सेमेस्टर की 26 मई से 16 जून, इसके आठवें सेमेस्टर की परीक्षाएं 30 मई से 16 जून और 10वें सेमेस्टर की परीक्षाएं 25 मई से तीन जून तक होंगी।

लखनऊ: शिया-सुन्नी चांद कमेटियों का बड़ा ऐलान, 27 मई नहीं इस तारीख को मनाई जाएगी बकरीद

(जीएनएस)। लखनऊ: शिया-सुन्नी चांद कमेटियों का बड़ा ऐलान, 27 मई नहीं इस तारीख को मनाई जाएगी बकरीद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिया-सुन्नी चांद कमेटियों ने जिले हिज्ज के चांद को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली और सैफ अब्बास ने किया ऐलान किया कि इस साल बकरीद 28 मई को मनाई जाएगी। मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने बताया कि रविवार 17 मई को जिले हिज्ज का चांद नहीं दिखाई दिया है। ऐसे में 28 मई को ईद-उल-अजहा



(बकरीद) का त्योहार मनाया जाएगा। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने बताया कि 19 मई को जिले हिज्ज की पहली तारीख होगी। वहीं

मनाने की अपील की है, वहीं चांद के ऐलान के बाद मुस्लिम समुदाय में बकरीद की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। शहर के बाजारों में खरीदारी बढ़ने लगी है और कुबानों को लेकर लोग आवश्यक इंतजामों में जुट गए हैं। बता दें कि बकरीद इस्लाम धर्म का प्रमुख त्योहार माना जाता है, जिसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुबानों की याद में मनाया हजारत जाता है। इस मौके पर मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अद करने के बाद कुबाना करते हैं और गरीबों व जरूरतमंदों के बीच मांस तकसीम किया जाता है।

लखनऊ में पुराने हाईकोर्ट के पास अवैध कब्जा हटाने पर बवाल, वकीलों के हंगामे पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज



लखनऊ के कैसरबाग पुराने हाईकोर्ट भवन के पास अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई शुरू हुई, जिसका वकीलों ने विरोध किया और पुलिस ने उन्हें खदेड़ा। (जीएनएस)। लखनऊ। आज रविवार सुबह नौ बजे से कैसरबाग पुराने हाईकोर्ट भवन के चारों से अवैध कब्जों को हटाया जाने लगा। कार्रवाई के विरोध में वकीलों का प्रदर्शन, पुलिस बल से खदेड़ा। हालांकि वकीलों का किसी तरह का विरोध न हो, इसके लिए पर्याप्त पुलिस बल का इंतजाम किया गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हो रही है। जिसमें अधिकांश अवैध चैंबर वकीलों के ही हैं। हालांकि कोर्ट में नगर निगम ने 72 अवैध कब्जेदारों की सूची दी थी लेकिन बाद में हुए सर्वे में अवैध कब्जों की संख्या दो सौ के करीब पाई गई थी, जिसमें सुरेंद्र नाथ रोड पर 72, स्वास्थ्य भवन से बीएसएनएल भवन की दीवार से कलेक्ट्रेट चौराहे और चक्रवर्त रोड तक 47, राजस्व परिषद से स्वास्थ्य भवन तक 25 और नाले के ऊपर



पचास से अधिक कब्जे थे। हालांकि नगर निगम की तरफ से सोलह मई तक कब्जे हटाने की नोटिस देने और लाल निशान लगाने के कारण कई वकीलों ने चैंबर से जालियां हटा ली थी। अवैध कब्जों को हटाने का दिया था आदेश न्यायमूर्ति राजेश सिंह चौहान और न्यायमूर्ति राजीव भारती की पीठ ने अधिवक्ता अनुराधा सिंह, अधिवक्ता देवांशी श्रीवास्तव और देवांशी की माता अरुणिमा श्रीवास्तव की तरफ से दाखिल याचिका पर सुनवाई के दौरान कचहरी रोड से अवैध कब्जों को हटाने का आदेश दिया था, लेकिन नगर निगम ने यह कहकर कोई कार्रवाई नहीं की थी कि पर्याप्त पुलिस बल के बिना अवैध कब्जों को हटाना संभव नहीं है। अगली सुनवाई में कोर्ट ने जिला प्रशासन को पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध कराने के साथ ही 25 मई को कार्रवाई से जुड़ी रिपोर्ट भी तलब की है। याचिका में अवैध कब्जों की आड़ में हो रही अराजकता का जिक्र किया था।

दिल्ली बनेगी 'तंदूर'! अगले हफ्ते 45डिग्री तक पहुंचेगा पारा, आईएमडी ने दी भीषण चेतावनी

(जीएनएस)। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राजधानी दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत के लिए बड़ी चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिनों में दिल्ली में गर्मी खतरनाक स्तर तक पहुंच सकती है और तापमान 45 डिग्री सेल्सियस को छू सकता है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि सोमवार (17 मई) से राजधानी में लगातार हीटवेव जैसे हालात बनेंगे। दिन का तापमान 43°C से 45°C के बीच रह सकता है, जबकि रात में भी राहत मिलने की उम्मीद कम है। न्यूनतम तापमान 25°C से 27°C के बीच रहने का अनुमान है। दिल्ली में अभी मई की शुरूआत वाली गर्मी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी कि अब उत्तर-पश्चिम से आने वाली गर्म और सूखी हवाओं ने हालात और मुश्किल बना दिए हैं। ऐसे में आनेवाला सप्ताह लोगों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण हो सकता है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक हवा का पैटर्न अचानक बदल गया है। पहले जहां पूर्वी हवाएं कुछ नमी लेकर आ रही थीं, वहीं अब पश्चिमी और राजस्थान की तरफ से उत्तर-पश्चिमी गर्म और शुष्क हवाएं दिल्ली की ओर बढ़ रही हैं। स्काईमेट वेदर के अध्यक्ष महेश



पलावत के मुताबिक यही वजह है कि तापमान तेजी से बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों में लू चलने की पूरी संभावना है। इन हवाओं का असर सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में भी तापमान तेजी से बढ़ सकता है। आईएमडी ने यह भी कहा है कि दिन के समय 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सतही हवाएं चल सकती हैं।

'हालात नहीं बदले तो करोड़ों लोग होंगे गरीब', पीएम मोदी की चेतवानी का क्या है मतलब ? अब किस आपदा की हो रही बात ?

(जीएनएस)। दुनिया इस वक्त सिर्फ जंग नहीं, बल्कि एक साथ कई बड़े संकटों से गुजर रही है। कहीं तेल सप्लाई का खतरा है, कहीं महंगाई लोगों की कमर तोड़ रही है, तो कहीं अर्थव्यवस्थाएं दबाव में हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में ऐसा बयान दिया, जिसने वैश्विक हालात को लेकर नई बहस छेड़ दी। पीएम मोदी ने साफ कहा कि अगर दुनिया ने तेजी से हालात नहीं बदले, तो पिछले कई दशकों की उपलब्धियां खत्म हो सकती हैं और करोड़ों लोग फिर गरीबी में धकेले जा सकते हैं। पीएम मोदी का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पश्चिम एशिया में

तनाव, तेल संकट, महंगाई और सप्लाई चैन की दिक्कतों ने दुनिया भर की सरकारों को चिंता बाढ़ा दी है। हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया लगातार नए संकटों का सामना कर रही है। पहले कोरोना महामारी आई, उसके बाद अलग-अलग हिस्सों में युद्ध शुरू हुए और अब ऊर्जा संकट पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा दशक धीरे-धीरे "आपदाओं का दशक" बनता जा रहा है। अगर हालात को जल्दी नहीं बदला गया, तो

कई देशों में गरीबी फिर तेजी से बढ़ सकती है। पीएम मोदी का यह बयान सीधे तौर पर उस वैश्विक माहौल की तरफ इशारा माना जा रहा है, जहां हुए पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया लगातार नए संकटों का सामना कर रही है। पहले कोरोना महामारी आई, उसके बाद अलग-अलग हिस्सों में युद्ध शुरू हुए और अब ऊर्जा संकट पूरी दुनिया के सामने खड़ा है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है, तो उसका

फायदा पूरी मानवता को मिलता है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा समय में दुनिया "रेंजिलिएर सप्लाई चैन" यानी भरोसेमंद और मजबूत सप्लाई नेटवर्क की बात कर रही है। इसी दिशा में भारत और नीदरलैंड मिलकर पारदर्शी और भविष्य के लिए तैयार सप्लाई चैन बनाने पर काम कर रहे हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि कोरोना महामारी के बाद दुनिया ने समझा कि किसी एक देश या क्षेत्र पर ज़रूरत से ज्यादा निर्भरता खतरनाक हो सकती है। यही वजह है कि भारत अब ग्लोबल सप्लाई चैन में खुद को मजबूत विकल्प के तौर पर पेश कर रहा है।



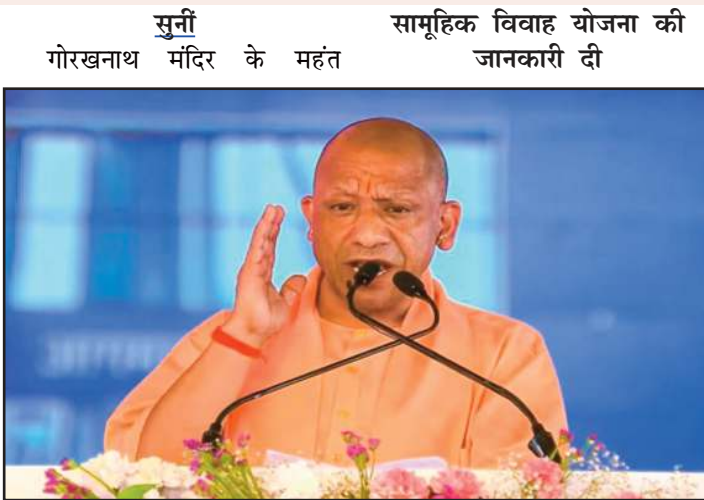
आशंका ने दुनिया भर में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ा मुद्दा बना दिया है। पीएम मोदी ने अपने भाषण में भारत की बढ़ती वैश्विक भूमिका पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब भारत आगे बढ़ता है, तो उसका

सीएम योगी का निर्देश- बिना भेदभाव हर जरूरतमंद को मिले न्याय

(जीएनएस)। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर प्रवास के दौरान लगातार दूसरे दिन रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में विभिन्न जिलों से आए लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति की समस्या का समाधान सरकार की प्रतिबद्धता है।

अधिकारियों को त्वरित निस्तारण के निर्देश
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे पूरी तत्परता और संवेदनशीलता से यह सुनिश्चित करें कि बिना भेदभाव सबको न्याय मिले। हर पात्र व्यक्ति को जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिले, जरूरतमंदों के समुचित इलाज की व्यवस्था हो और जमीन कब्जाने वाले भू-माफिया व दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

करीब 150 लोगों की समस्याएं



दिव्यजयनाथ स्मृति भवन के बाहर आयोजित जनता दर्शन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 150 लोगों की समस्याएं सुनीं। उन्होंने के समुचित इलाज की व्यवस्था हो और जमीन कब्जाने वाले भू-माफिया व दबंगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए।

सुनीं गोरखनाथ मंदिर के महंत

सामूहिक विवाह योजना की जानकारी दी

जनता दर्शन में एक महिला ने परिवार की कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए बेटी की शादी के लिए सहायता मांगी। इस पर मुख्यमंत्री ने उसे प्रति जोड़ा एक लाख रुपए सहायता वाली सामूहिक विवाह योजना की जानकारी दी। महिला ने अपनी बेटी को भी योजना का लाभ दिलाने का अनुरोध किया,

जिस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए।

इलाज के लिए आर्थिक मदद का भरोसा

गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने पहुंचे लोगों से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि धन के अभाव में किसी का इलाज नहीं रुकेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जरूरतमंद मरीजों के इलाज का इस्टीमेट जल्द तैयार कर उपलब्ध कराया जाए, ताकि सरकार तुरंत आर्थिक सहायता जारी कर सके।

कानून व्यवस्था और राजस्व मामलों पर भी सख्ती

राजस्व और कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

ब्रिटेन में तख्तापलट की तैयारी! कुर्सी छोड़ने को तैयार ब्रिटिश पीएम कीर स्टारमर, क्यों बने ऐसे हालात?

(जीएनएस)। यूनाइटेड किंगडम में इन दिनों भारी सियासी ड्रामा चल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने संकेत दिए हैं कि वह पद छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह यह फैसला सम्मानजनक तरीके से अपनी शर्तों पर लेना चाहते हैं।

चुनाव में मिली हार, कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे और जेफरी एपस्टीन विवाद के कारण लेबर पार्टी की सरकार चौतरफा दबाव में है। जनता में स्टारमर की लोकप्रियता तेजी से गिर रही है, जिससे ब्रिटेन में एक बार फिर सत्ता बदलने की सुगुणाहट तेज हो गई है।

क्यों उठ रहे हैं इस्तीफे के सवाल?

डेली मेल की रिपोर्ट के मुताबिक, पीएम कीर स्टारमर को भी यह अहसास हो गया है कि मौजूदा राजनीतिक हालात लंबे समय तक नहीं चल सकते। लेबर सरकार इस समय कई विवादों से घिरी हुई है।

पीटर मैडेलसन की नियुक्ति और उनका नाम जेफरी एपस्टीन विवाद से



जुड़ने के कारण जनता में काफी गुस्सा है। इसके अलावा हालिया लोकल चुनावों में पार्टी के खराब प्रदर्शन ने आग में घी का काम किया है, जिससे स्टारमर पर दबाव बढ़ गया है।

अपनी ही कैबिनेट से मिली चुनौती

लेबर सरकार को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब पूर्व हेल्थ सेक्रेटरी वेस स्ट्रीटिंग ने कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने खुलकर कहा

कि अगर भविष्य में पार्टी के भीतर लीडरशिप का चुनाव होता है, तो वह

लोग कीर स्टारमर को पसंद नहीं कर रहे हैं। उनकी तुलना देश की पूर्व पीएम लिज ट्स से की जा रही है, जिनका कार्यकाल सिर्फ 49 दिनों का था। लेबर सांसदों को डर है कि अगर स्टारमर पद पर बने रहे, तो अगली बार सरकार बनाना मुश्किल होगा और इसका सीधा फायदा दक्षिणपंथी नेता निगेल फराज को मिल सकता है।

पीएम स्टारमर का क्या है कहना?

इन तमाम अटकलों और सामाजिक तनाव के बीच प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने भी अपनी बात रखी है। उन्होंने कहा कि देश में शांतिपूर्ण विरोध का हमेशा स्वागत है, लेकिन कुछ लोग समाज में नफरत और बंटवारा फैला रहे हैं। उन्होंने साफ किया कि ब्रिटेन में उग्र विचार फैलाने की कोशिश कर रहे कुछ कट्टरपंथी विदेशी आंदोलनकारियों के वीजा सरकार ने पहले ही रोक दिए हैं, क्योंकि वे देश की पहचान और सभ्यता के खिलाफ हैं।

सर्वे में लोकप्रियता का ग्राफ गिरा

YouGov UK के नए सर्वे ने लेबर पार्टी की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सर्वे के अनुसार, करीब 69 फीसदी ब्रिटिश

लखनऊ: पति से विवाद के बाद युवती पानी की टंकी पर चढ़ी, आत्महत्या की धमकी दी, पुलिस ने उतारा

(जीएनएस)। लखनऊ। गोमती नगर के विनीत खंड पांच में रविवार को एक युवती पानी की टंकी पर चढ़ गईं। टंकी पर चढ़ी युवती नीचे कूद कर आत्महत्या की धमकी देने लगीं। आसपास लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवती को समझाने का प्रयास किया। काफी देर समझाने के बाद पुलिस ने उसे नीचे उतारा।

गोमती नगर इस्पेक्टर ब्रजेश चंद्र तिवारी ने बताया कि अयोध्या के एक गांव निवासी युवती का लखीमपुर



निवासी युवक से प्रेम विवाद हुआ था। बीच किसी बात को लेकर विवाद दोनों लखनऊ में रहते थे। दोनों के

खंड पांच स्थित पानी की टंकी पर चढ़ गईं। उसने टंकी पर चढ़कर शोर मचाते हुए आत्महत्या करने की बात कही।

यह सुनकर आसपास के लोग एकत्रित हो गए। उनकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। काफी देर तक पुलिस युवती को समझाने का प्रयास करती रही। मान-मनौचल के बाद महिला पुलिसकर्मियों ने किसी तरह उसे नीचे उतारा। इसके बाद उसे गोमती नगर थाने ले जाया गया। पुलिस युवती से पूछताछ कर रही है।

पंजाब से बिहार-UP होते हुए बंगाल तक चलेगी नई ट्रेन, रूट में शामिल हैं कौन से 35 स्टेशन?

(जीएनएस)। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए एक नई लंबी दूरी की सुविधा शुरू करने की तैयारी कर ली है, जो पंजाब और पश्चिम बंगाल को सीधे जोड़ेगी। अमृतसर से न्यू जलपाईगुड़ी (एनजेपी) के बीच चलने वाली अमृत भारत एक्सप्रेस जल्द ही व्यावसायिक संचालन शुरू करने जा रही है। यह ट्रेन उत्तर भारत और पूर्वी भारत के बीच यात्रा को आसान और अधिक किफायती बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है।

चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (ICF) में बनी यह ट्रेन आधुनिक डिजाइन और बुनियादी सुविधाओं के साथ तैयार की गई है, जिसमें आराम और बजट दोनों का ध्यान रखा गया है। यह सेवा खासकर उन यात्रियों के लिए राहत लेकर आई है जो नियमित रूप से लंबी दूरी की यात्रा करते हैं और सस्ते लेकिन भरोसेमंद विकल्प की तलाश में रहते हैं।

सप्ताहिक संचालन और ट्रेन नंबर

एक बार चलेगी। ट्रेन संख्या 14664 अमृतसर से हर गुरुवार दोपहर रवाना होगी, जबकि ट्रेन संख्या 14663 न्यू जलपाईगुड़ी से हर शनिवार सुबह यात्रा शुरू करेगी। यह साप्ताहिक



संचालन यात्रियों को एक तय और स्थिर यात्रा विकल्प प्रदान करेगा, जिससे वे अपनी यात्रा पहले से योजना बना सकेंगे।

लंबी दूरी की समय-सारिणी
इस ट्रेन की यात्रा समय लंबी दूरी को ध्यान में रखते हुए तय की गई है। न्यू जलपाईगुड़ी से चलने वाली ट्रेन शनिवार सुबह 08:00 बजे रवाना होकर सोमवार रात 02:20 बजे

अमृतसर पहुंचेगी। वहीं अमृतसर से रवाना होने वाली ट्रेन गुरुवार दोपहर 12:45 बजे शुरू होकर शनिवार सुबह 04:15 बजे न्यू जलपाईगुड़ी पहुंचेगी। इस लंबे सफर के दौरान यात्रियों को

बिहार और पश्चिम बंगाल के कई महत्वपूर्ण स्टेशन शामिल हैं। प्रमुख ठहरावों में जालंधर सिटी, लुधियाना, अंबाला, कैट, सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, सीतापुर, गांंडा, बड़नी, गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल, सीतामढ़ी, फारबिसगंज, अररिया, बागडोगरा और सिलीगुड़ी जैसे स्टेशन शामिल हैं, जो इस रूट को और अधिक महत्वपूर्ण बनाते हैं।

बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बढ़ेगी सुविधा

इस नई ट्रेन सेवा का सबसे बड़ा लाभ बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के यात्रियों को मिलने की उम्मीद है। इन क्षेत्रों के कई छोटे शहर और कस्बे लंबे समय से सीधे लंबी दूरी की ट्रेनों की कमी महसूस कर रहे थे। इस सेवा के शुरू होने से गोरखपुर, नरकटियागंज, रक्सौल और आसपास के क्षेत्रों के यात्रियों को पंजाब और पश्चिम बंगाल तक सीधी यात्रा का विकल्प मिलेगा, जिससे उनकी यात्रा का समय और कठिनाई दोनों कम होंगे।

लखनऊ जंक्शन पर 70 यात्रियों के लिए अस्थायी प्रतीक्षालय शुरू

(जीएनएस)। लखनऊ। लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए अस्थायी प्रतीक्षालय रविवार से शुरू कर दिया गया है। इसकी क्षमता 70 यात्रियों की है। प्रतीक्षालय पूरी तरह से निःशुल्क रहेगा। इसमें बैठने की व्यवस्था के साथ शौचालय, चार्जर आदि सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी।

वीते बृहस्पतिवार को पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के लखनऊ जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बने महिला प्रतीक्षालय को छत उस वक्त गिर गई थी, जब इसके विस्तार के

लिए दीवार व पिलर तोड़े जा रहे थे। छत गिरने से हड़कंप मच गया।



हालांकि कोई यात्री चोटिल नहीं हुआ। उस वक्त महिला प्रतीक्षालय व प्रथम तल पर बने एसी वेटिंग रूमों में करीब दो सौ यात्री थे, जिन्हें सकुशल सुरक्षित जगह पर

दिया गया था। इस मुद्दे को अमर उजाला लखनऊ संस्करण के माई सिटी में प्रमुखता से उठाया गया था कि प्रतीक्षालय बंद होने से यात्रियों के पास बैठने की व्यवस्था नहीं है, उन्हें

प्लेटफॉर्म पर ट्रेनों का इंतजार करना पड़ रहा है। इसी क्रम में पूर्वोत्तर रेलवे प्रशासन ने रिवार को अस्थायी प्रतीक्षालय शुरू कर दिया है। जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता ने बताया कि प्लेटफॉर्म नंबर छह पर ऐरावत हेरिटेज इंजन के पास अस्थायी रूप से रेलयात्रियों के लिए अस्थायी प्रतीक्षालय बनाया गया है। इसकी क्षमता 70 यात्रियों की है। प्रतीक्षालय की सुविधा निःशुल्क रहेगी। इसमें बैठने की व्यवस्था के साथ टॉयलेट, मोबाइल चार्जर, पंखे, मेज आदि सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी।

78 हजार वोटों की जीत, अब उतने ही पेड़ लगाने का संकल्प, विधायक सुहास बाबर की अनोखी पहल

(जीएनएस)। सांगली जिले में पर्यावरण संरक्षण को जनआंदोलन का रूप देने वाली एक अनोखी पहल तेजी से आगे बढ़ रही है। विधायक सुहास बाबर के नेतृत्व में शुरू हुआ यह अभियान अब हजारों नागरिकों की भागीदारी वाली 'ट्री आर्मी' बन चुका है। इस अभियान का मूल उद्देश्य है - किसी भी पीपल के पेड़ को काटने के बजाय उसका पुनर्स्थापन करना और हरित वातावरण को संरक्षित करना।

खानापूर-आटपाडी क्षेत्र में शुरू हुआ यह हरित आंदोलन आज पूरे सांगली जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। विधायक सुहास बाबर ने बताया कि एक पीपल के पेड़ के पुनर्वसन से मिली प्रेरणा ने अब व्यापक जनभागीदारी वाले पर्यावरण अभियान का रूप ले लिया है। लोगों में इस पहल को लेकर इतना उत्साह है कि वे स्वच्छ से जमीन, पानी, पौधे और श्रमदान उपलब्ध करा रहे हैं।

स्वर्गीय विधायक अनिलभाऊ बाबर की पर्यावरण और मिट्टी से जुड़ी

सोच को आगे बढ़ाते हुए विधायक सुहास बाबर ने 2024 विधानसभा चुनाव में मिली 78,178 वोटों की बढ़त



के बराबर पेड़ लगाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि "पीपल की कहानी" सोशल मीडिया पर साझा करने के बाद इस अभियान को अभूतपूर्व प्रतिसाद मिला और हजारों लोग इससे जुड़ गए। लोगों ने ही इस अभियान को 'ट्री आर्मी' नाम दिया।

इस अभियान के तहत विभिन्न सामाजिक और व्यक्तिगत स्तर पर भी सराहनीय योगदान सामने आ रहे हैं।

विधायक सुहास बाबर ने अपनी माताजी के श्राद्ध दिवस पर 5,300 आम के पौधे लगाए। वहीं विटा नगर

परिषद के एक नगरसेवक ने चार वर्ष पुराने 52 पेड़ इस अभियान को समर्पित किए, जबकि आलसंद ग्राम पंचायत ने 500 पौधों का रोपण किया है। सांगली जिला प्रशासन और वन विभाग के सहयोग से एक एकड़ भूमि पर जापानी पद्धति के 'मियावाकी जंगल' विकसित करने की योजना भी बनाई गई है। इसके साथ ही चरागाह भूमि और सड़कों के किनारे स्थानीय

जलवायु के अनुरूप बड़े और छायादार वृक्ष लगाने का अभियान शुरू किया गया है। पहले सड़कों के किनारे दिखाई देने वाली हरित सुरंगें (ग्रीन टनल), जो यात्रियों को छाया और ठंडक देती थीं, सड़क चौड़ीकरण के कारण समाप्त हो गई थीं। अब उन्हें फिर से पुनर्जीवित करने का लक्ष्य रखा गया है।

आगामी 5 जून, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वट, पीपल, बहावा, करंज और इमली जैसे बड़े एवं छायादार वृक्षों का बड़े पैमाने पर रोपण किया जाएगा। इनके संरक्षण और संवर्धन के लिए 'ट्री आर्मी' पूरी तरह प्रतिबद्ध है। जिले के व्यापारी संगठन, सामाजिक संस्थाएं और विभिन्न नागरिक भी इस अभियान में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। विधायक सुहास बाबर ने खानापूर-आटपाडी क्षेत्र से रोजगार के लिए बाहर रहने वाले लोगों से भी इस हरित अभियान से जुड़ने और अपने गांव से पुनः भावनात्मक रिश्ता मजबूत करने की अपील की है।

टीएमसी ऑफिस में मिले ढेरों आधार कार्ड कोलकाता में मचा हड़कंप, आखिर पार्टी दफ्तर में क्यों रखे थे पहचान पत्र?

(जीएनएस)। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने राजनीति और पहचान दस्तावेजों की सुरक्षा को लेकर नई बहस छेड़ दी है। कोलकाता के बिधाननगर इलाके में स्थित तुणमूल कांग्रेस (TMC) के एक स्थानीय पार्टी कार्यालय से कई आधार कार्ड मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

यह मामला सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर इतने संवेदनशील दस्तावेज किसी राजनीतिक पार्टी कार्यालय में क्यों रखे गए थे और क्या यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही थी या फिर मामला इससे ज्यादा गंभीर है। बिधाननगर के टीएमसी ऑफिस से कैसे मिले आधार कार्ड जानकारी के मुताबिक यह बरामदगी बिधाननगर नगर निगम के वार्ड नंबर 36 स्थित एक स्थानीय टीएमसी कार्यालय में हुई। बताया जा

रहा है कि इलाके के कुछ लोगों को पार्टी दफ्तर के अंदर आधार कार्ड पड़े होने की जानकारी मिली, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलने के बाद बिधाननगर



साथ पुलिस स्टेशन की टीम मौके पर पहुंची और दस्तावेजों को अपने कब्जे में लेकर शुरुआती जांच शुरू कर दी। फिलहाल पुलिस ने यह साफ नहीं किया है कि कुल कितने आधार कार्ड बरामद हुए हैं। हालांकि अधिकारियों ने इतना जरूर कहा है कि सभी दस्तावेजों की जांच की जा रही है और यह पता लगाने की

कोशिश हो रही है कि उन्हें वहां क्यों रखा गया था।

स्थानीय लोगों ने क्या दावा किया?

इलाके के कई लोगों का कहना है

गए होंगे। हालांकि यह सिर्फ स्थानीय लोगों की तरफ से कही गई बातें हैं और पुलिस अभी इन दावों की पुष्टि कर रही है। यही वजह है कि अब जांच इस बात पर केंद्रित है कि क्या दस्तावेज अस्थायी तौर पर रखे गए थे या फिर किसी प्रक्रिया में गंभीर लापरवाही हुई। पुलिस किन बिंदुओं पर जांच कर रही है?

पुलिस अब कई अहम पहलुओं की जांच कर रही है। अधिकारियों के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि आधार कार्ड वहां कैसे पहुंचे और क्या इनका किसी गलत काम में इस्तेमाल हुआ।

जांच में मुख्य रूप से इन बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है:

आधार कार्ड किसके हैं

दस्तावेज पार्टी कार्यालय में क्यों रखे गए थे

क्या किसी तरह की अनियमितता हुई

क्या दस्तावेजों का गलत इस्तेमाल किया गया

क्या आधार से जुड़ी प्रक्रिया नियमों के मुताबिक हुई

अब तक पुलिस ने यह जानकारी नहीं दी है कि मामले में कोई एफआईआर दर्ज की गई है या नहीं। आधार कार्ड इतना संवेदनशील दस्तावेज क्यों है?

भारत में आधार कार्ड सबसे अहम पहचान दस्तावेजों में गिना जाता है। इसमें व्यक्ति की बायोमेट्रिक और व्यक्तिगत जानकारी जुड़ी होती है। यही कारण है कि आधार से जुड़े दस्तावेजों की सुरक्षा और गोपनीयता को बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है।

विशेषज्ञों का कहना है कि किसी भी संस्था, कार्यालय या संगठन के पास लोगों के पहचान दस्तावेज लंबे समय तक बिना स्पष्ट प्रक्रिया के रखना चिंता का विषय बन सकता है। इससे प्राइवैसी, डेटा सुरक्षा और पहचान के दुरुपयोग जैसे सवाल खड़े हो सकते हैं।

राजनीतिक दफ्तरों की भूमिका पर भी उठे सवाल

यह मामला सिर्फ आधार कार्ड मिलने तक सीमित नहीं है। इस घटना ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है कि कई इलाकों में राजनीतिक कार्यालय लोगों के दस्तावेजों का कामों में कितनी भूमिका निभाते हैं।

'20 साल हो गए मुझे,' कोहली ने पंजाब के खिलाड़ी को किया स्लेज, वीडियो देख फैस ने ठोका सलाम

(जीएनएस)। आईपीएल में खिलाड़ियों के बीच मुकाबला सिर्फ बल्ले और गेंद का नहीं होता, बल्कि शब्दों का भी होता है। ऐसा ही एक दिलचस्प नजारा धर्मशाला के खूबसूरत मैदान पर देखने को मिला था, जब रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु (RCB) के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और पंजाब किंग्स के स्पिनर हरप्रीत बरार के बीच नोकझोंक हो गई।



अमूमन शांत दिखने वाले बरार को विराट ने अपने ही अंदाज में ऐसा जवाब दिया कि स्टैंप माइक पर रिकॉर्ड हुई उनकी आवाज सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। हालांकि यह हल्की बातचीत गुस्से वाली नहीं थी, बल्कि मजाक वाली लग रही थी। मैच के दौरान जब पंजाब के स्पिनर हरप्रीत बरार अपनी गेंदबाजी से विराट को बांधने की कोशिश कर रहे थे, तब 'किंग कोहली' अलग ही मूड में थे। बरार की एक गेंद को खेलने के बाद विराट ने मुस्कुराते हुए पंजाबी लहजे में उन्हें चुनौती दे डाली।

विराट ने कहा कि 20 साल हो गए खेलते हुए, ऐसे आउट नहीं होऊंगा।

हर बार की तरह आज भी कोहली का बल्ला जमकर चला और पंजाब किंग्स के गेंदबाज सिर्फ देखते चले गए। कोहली ने फिफ्टी जमाई और इस सब उन्होंने पंजाबी भाषा में कहा। दरअसल बरार ने इससे पहले कोहली को रन आउट करने का प्रयास किया था। इस पर कोहली उनको धरते रहे और रन आउट करने के लिए थ्रो फेंकने की चुनौती दे डाली। बरार को पता था कि थ्रो करने पर कोहली क्रीज में आ जाएंगे, इस वजह से उन्होंने कुछ नहीं किया।

किंग्स के गेंदबाज सिर्फ देखते चले गए। कोहली ने फिफ्टी जमाई और इस सब उन्होंने पंजाबी भाषा में कहा। दरअसल बरार ने इससे पहले कोहली को रन आउट करने का प्रयास किया था। इस पर कोहली उनको धरते रहे और रन आउट करने के लिए थ्रो फेंकने की चुनौती दे डाली। बरार को पता था कि थ्रो करने पर कोहली क्रीज में आ जाएंगे, इस वजह से उन्होंने कुछ नहीं किया।